कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

वर्ष 56 | अप्रैल, 2011 | अंक 4

सभापति का पत्र :

बजट में हमेशा की तरह से उल्लेख किसानों का है लेकिन ध्यान कहीं और। सरकार भी महाभारत में कुरूक्षेत्र के युद्ध के दौरान राजा युधिष्ठिर की तरह कह रही है, जैसे उन्होंने जोर से घोषणा करी थी की 'अश्वात्थामा हत्था' और धीरे से कहा 'नारो वा कुंजारो'। जोर से उन्होंने कहा था कि योद्धा का पुत्र अश्वात्थामा मर चुका है, और जो वो सुनाना नहीं चाहते थे इसलिऐ धीरे से फुसफुसाऐ कि 'महान योद्धा हो या फिर हाथी'। जोर से बोले गऐ झूठ को सुनकर ही अश्वात्थामा के पिता तथा कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य युद्ध छोड़कर ध्यान लगाने बैठे तभी पांड़व सेना के धीष्टादयुमना ने पूर्ण छल के साथ उनकी हत्या कर दी। इसी तरह यह बजट दिखाने से ज्यादा छुपाता है।

अक्सर उल्लेख किया जाता है कि 'खाद्य मुद्रास्फीति' आज एक प्रमुख चिंता का विषय है। जरा खाद्य मुद्रस्फीति पर किसानों की दृष्टि से विचार करते हैं, 'सन् 1981 में जब मैं अजमेर में स्कूल में था तब मुझे अपने बड़ो द्वारा बताया गया कि सोने और कपास दोनों का भाव रू. 400/– प्रति ग्राम तथा प्रति क्विंटल कमशः है।' आज 30 साल बाद मैंने अपनी कपास की फसल रू. 4,000/– पर बेची तथा सोने का भाव रू. 22,000/– है। इसका मतलब यह हुआ कि इस दौरान कपास और सोने दोनों का भाव 10 तथा 55 गुणा बढ़ा। सोने को हम धन मापने के मानक के रूप में जानते हैं, इसलिऐ हम किसान चिंतित हैं। बजट विकास के लिऐ अवसर बनाता है, लेकिन यह बजट किसानों के लिऐ खोऐ अवसरों से अधिक है।

बहुत से लोग कृषि मंत्रालय के लिऐ एक अलग बजट की मांग करते हैं। बजट राजस्व और व्यय में संतुलन बनाने की एक प्रकिया है। बजट भाषण में सरकार अपने प्रयासों और धन आबंटन की विवशता को समझाती है। कृषि मंत्रालय के पास अपने राजस्व को बढ़ाने का कोई स्रोत्र नहीं है, इसलिऐ उनके पास अपना खुद का बजट नहीं है।

समाज के वरिष्ठ सदस्य श्री के.के. अग्रवाल ने भारत कृषक समाज की जबलपुर, (म.प्र.) में एक बैठक का आयोजन किया तथा 'कृषक शक्ति' पत्रिका का विमोचन किया। मुझे नेफेड़ द्वारा 'कृषि विपणन सुधारों' पर आयोजित राऊंडटेबल में भाग लेने का मौका

मिला। मैंने एशियन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बैंकॉक, थाईलैंड़ में आयोजित 'सहायक दक्षिणी यूरोपीय गठबंधनों / एआरडी प्लेटफॉर्म' कार्यशाला में भी हिस्सा लिया।

अजय जाखड़
अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

फॉर्मर्स फोरम पत्रिका में प्रकाशित लेखों का सार

कृषि : एक तरफ किनारे कर दिया गया

*** नरेश मनोचा**

बजट जो कहता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वह है कि बजट जो कुछ नहीं कहता है। निर्माण क्षेत्र और तेजी से बढ़ते हुए सेवा क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र काफी पीछे है। इससे स्थिति और भी चिंताजनक है कि कृषि के विकास का स्तर समग्र सकल घरेलू उत्पाद वशद्धि में कम होता जा रहा है। ऐसा तब हो रहा है जब यूपीए सरकार वर्ष 2004 के मध्य से पूरा प्रयास इस दिशा में कर रही है उस वर्ष जब वह पहली बार सत्ता में लौटी थी।

कशषि घरेलू सकल उत्पाद में वार्षिक औसत वृद्धि 2.9 प्रतिशत रही जबकि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाली ग्यारवहीं पंचवर्षीय योजना में 4 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। यह स्पष्ट है कि वर्तमान परियोजनाओं और योजनाओं में घपला होने के कारण आने वाले बजटों में सन्तोषजनक परिणाम सामने नहीं आए, इन योजनाओं को दोबारा नाम दे दिया जाता और अलग प्रकार से बजट का आवंटन किया जाता रहा है।

डॉ० एम.एस. स्वामिनाथन, एक प्रतिष्ठित कृषि विशेषज्ञ और राज्य सभा के सदस्य ने बजट प्रस्तावों में अपनी चिंता व्यक्त की और अपना औपचारिक रिएक्शन भी दर्ज किया कि बजट में दूर दृष्टि का अभाव है और ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसानों को खेतों तक ही सीमित रखा जाए और कृषि क्षेत्र में युवाओं को भी आकर्षित किया जा सके।

यू.पी.ए. सरकार के प्रमुख कार्यकम में आबंटन में वृद्धि की घोषणा की गई तथा राष्ट्रीय कशषि विकास योजना को वर्ष 2010–11 में 6755 करोड़ रू. आबंटित किए गए थे जिसे वर्ष 2011–12 के दौरान 7660 करोड़ कर दिया गया। कुछ अन्य योजनाएं भी सामने आई जिनमें 300 करोड़ रू. से अधिक का व्यय होने का अनुमान है, वे हैं शहरों के आस–पास सब्जी कलस्टर की संख्या बढ़ाना, प्रोटिन सप्लीमेंट्स पर नैशनल मिशन, न्यूट्री–सीरियल्स (जैसे बाजरा) का उत्पादन बढ़ाने की योजना, पाम तेल के पौधों में वृद्धि की योजना, चारा विकास कार्यकम में वृद्धि करना।

वित्त मंत्री ने कृषि ऋण को बांटने के लक्ष्य को 3,75,000 करोड़ रू. से बढ़ाकर 4,75,000 करोड़ रू. करने की घोषणा की। उन्होंने उन किसानों को एक प्रतिशत की ब्याज दर में कमी का भी अवसर दिया है जिन्होंने पहले से लिया गया ऋण समय पर

वापस कर दिया है। उन्हें वर्तमान में 2 प्रतिशत ब्याज दर में कमी की सुविधा मिल रही है। श्री मुखर्जी ने ऋण के समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करके 3 प्रतिशत कर दिया है, इस प्रकार लघु कालिक फसल ऋण की ब्याज दर कम कर दी है और यह 7 प्रतिशत से केवल 4 प्रतिशत रह गई है। किन्तु श्री मुखर्जी ने यह नहीं बताया कि 4 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश अक्तूबर 2006 में किसानों के राष्ट्रीय कमीशन द्वारा की गई थी। इस प्रकार यू.पी.ए. सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने में साढ़े चार वर्ष का समय ले लिया।

श्री मुखर्जी द्वारा कतिपय कृषि योजनाओं के आबंटन के संबंध में चुनी हुई बातों से प्रतित होता है कि उन्होंने कृषि एवं सहकारिता विभाग और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के कुल आबंटन में कटौती की है :

- कृषि एवं सहकारिता विभाग के आबंटन में 0.97 प्रतिशत कमी करके वर्ष 2011–12 में 17522.87 करोड़ रू. कर दिया गया जबकि संशोधित प्रावधान 17695.48 करोड़ रू. का था।
- कृषि अनुसंधान एंव शिक्षा विभाग का व्यय 4.02 प्रतिशत घटाया गया और यह 4957 करोड़ रू. किया गया जबकि संशोधित अनुमान 5165 करोड़ रू. का था।

किन्तु वित्त मंत्री ने पशुपालन विभाग, डेरी और मछली पालन के आबंटन में 25.11 प्रतिशत की वृद्धि की और यह 1696.25 करोड़ रू. हो गया जबकि संशोधित प्रावधान केवल 1355.7 करोड़ रू. का था। बजट में उर्वरक आर्थिक सहायता में भी 9 प्रतिशत की कटौती करके 49997.87 करोड़ रू. कर दिया गया जबकि वर्ष 2010–11 में संशोधित अनुमानित बजट 54976.68 करोड़ रू. का था। इसके अतिरिक्त इन्होंने खाद्य और जन वितरण विभाग (इसमें खाद्य भण्डारण और गोदाम शामिल) के कुल आबंटन में भी 9.4 प्रतिशत की कटौती की और यह 61606 करोड़ रू. हो गया जबकि संशोधित अनुमान 68021 करोड़ रू. का था।

फसल बीमा का सफाया

बजट के आंकड़ों के पहाड़ के नीचे फसल बीमा में जबरदस्त 63.63 प्रतिशत की कुल कटौती की गई और यह 3162 करोड़ रू. से घटकर 1150 करोड़ रू. रह गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में दिसम्बर, 2010 में प्रधानमंत्री को वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर प्रोडैक्शन ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें सिफारिश की गई कि 'सभी महत्वपूर्ण खाद्य फसलों और पशुधन के लिए एक बीमा नीति की आवश्यकता है जो वरीयता स्तर पर हो और इसके लिए केन्द्र से अतिरिक्त फंड़ देकर इसे गांव के रूप में एक यूनिट के आधार पर कियान्वित किया जाना चाहिए न कि ब्लॉक स्तर पर'।

उर्वरक पर प्रभाव

उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि यू.पी.ए. सरकार ने किसानों को विश्व मूल्य की तुलना में संवेदनशील बना दिया है और उर्वरक के क्षेत्र में जोखिमपूर्ण आपूर्ति होने

से भी मूल्यों में वृद्धि हो रही है क्योंकि सरकार नए यूरिया प्रोजैक्ट्स को गैस आबंटित करने में असफल रही और आर्थिक सहायता के क्षेत्र में भी यह सरकार दुविधा में है। यह आश्चर्य की बात है कि कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश कम करने से बहुराष्ट्रीय उर्वरक की कम्पनियों का ध्यान भारतीय बाजार की ओर आकर्षित हुआ है।

वर्ष 2010 की वार्षिक रिपोर्ट में कनाडा स्थित पोटाश कारपोरेशन ने नोट किया है कि भारत की डाईअमोनियम फास्फेट के आयात में वर्ष 2007 से लगभग 3 गुणा वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2010 में रिकॉर्ड़ 7.6 मिलियन टन तक पहुंच गई है। अब भारतीय कम्पनियाँ का विश्व सॉलिड़ फास्फेट कारोबार में लगभग 40 प्रतिशत भाग है। इसका कहना है कि 'भारत की बढ़ती हुई मांग विश्व व्यापार में मुख्य भूमिका निभा रही है'। यूरिया के आयात पर बढ़ती हुई निर्भरता की कहानी और एन.पी.के. कॉम्पलैक्स उर्वरक की कहानी लगभग एक सी है।

कशषि क्षेत्र में धीमे और कम वशद्धि तथा इसका खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव के परिणाम से नेताओं के विचारों में कोई अन्तर नहीं आया है। उनका ध्यान केवल सरकारी घाटे, नीतिपरक घाटे, बजट घाटे, भ्रष्टाचार और मुद्रा स्फीति पर ही केन्द्रित है।

सरकार को अगला बजट नेहरू जी की सोच के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए।

---

* लेखक एक वरिष्ठ पत्रकार है और टैक्सइण्डिया ऑन लाईनडाटकाम में कन्सलटिंग एडीटर है और जीफाईल्सइण्यिा में एसोसिएट एडीटर हैं।

बजट 2011–12 : हमेशा की तरह आम बजट

*** सुनित चोपड़ा**

इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ विशेष नहीं है। कृषि क्षेत्र को एक बार फिर इस बजट से निराशा हाथ लगी क्योंकि इसे वे संसाधन नहीं मिले जिनकी आवश्यकता थी जबकि घरेलू सकल उत्पाद में वर्ष 1991 में इसका 31.4% भाग था और वर्ष 2010 में यह कम होकर 14.2% रह गया, कृषि क्षेत्र देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या की पेट भरता है। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2010–11 के दौरान 17695 करोड़ रूपऐ आबंटित थे जो वर्ष 2011–12 में 17523 करोड़ रूपऐ रह गए जबकि ग्रामीण विकास में भी पिछले बजट में 89629 करोड़ रूपऐ से कम होकर 87845 करोड़ रूपऐ आबंटित किए गए। इसके अतिरिक्त उर्वरक में आर्थिक सहायता कम करके 9.4% और तेल पर अत्याधिक 38.5% की कमी की गई जो कुल कटौती 20,000 करोड़ रूपऐ बनती है। ग्रामीण लोगों के लिए यह विध्वंसक है जो 70% से अधिक ऐसे है जिन्हें 2200 केलोरी से कम मात्रा मिलती है और वर्ष 1991 से प्रत्येक वर्ष 33 लाख किसान भूमिहीन हो जाते हैं जिनसे हमारे गांव की निर्धनता का पता चलता है।

इस नीति से यह स्पष्ट है कि यदि सरकार कृषि क्षेत्र से अपना हाथ खेंचती है तो निजी निवेश उसका स्थान ले लेगा। हमारा प्रयास है कि ऐसा नहीं होगा इसके विपरीत कृषि

और ग्रामीण विकास में सरकारी निवेश के स्थान पर निजी निवेश अधिक किया जा रहा है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण लोगों को 4% की दर से ऋण दिया जाए यदि उन्होंने पहले का बकाया लौटा दिया है, इससे पहले उन्हें ऋण राहत कार्यक्रम से बाहर रखा गया था।

इसी प्रकार से ग्रामीण पेयजल के कार्यक्रम हेतु केवल 8099 करोड़ रूपऐ दिए गए। पिछले वर्ष में खर्च की गई राशि की तुलना में यह 400 करोड़ रूपऐ कम है। इन्द्रा आवास योजना भी 8996 करोड़ रूपऐ पर स्थिर रही। वर्तमान सरकारी नीतियों के कारण सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि होने से यह राशि इस कार्य के लिए अपर्याप्त है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी पिछले वर्ष के 19886 करोड़ रूपऐ के व्यय की तुलना में इस बार 18217 करोड़ रूपऐ आबंटित किए गए जो 1600 करोड़ रूपऐ कम है। प्रोटीन स्पलीमेंटस, जैविक कशषि के राष्ट्रीय मिशन और पूर्वी क्षेत्रों में हरित कांति लाना अच्छा लगता है किन्तु इस क्षेत्र में अत्यधिक बाढ़ के खतरों के कारण यहां सिंचाई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और ये योजनाऐं आरंभ ही नहीं हो पाती हैं। ग्रामीण आधार–भूत सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता को पूरा न कर पाने के कारण इसका रोजगार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन मनरेगा के वेतन को मुद्रास्फीति से जोड़ने पर भी इस योजना के व्यय को 100 करोड़ रूपऐ कम करके 40,000 करोड़ रूपऐ किया गया जबकि मंत्रालय ने 63,000 करोड़ रूपऐ की मांग रखी थी। इस प्रकार रोजगार क्षेत्र को बढ़ाने में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जा रहा।

इसका आवश्यक रूप में अर्थ है कि कशषि के कारपोरेटाईजेशन और कृषि बाजार में अटकलों से जल्दी–जल्दी बिकी और शीघ्र उत्पादन की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा पहले था। श्री अशोक गुलाटी, निदेशक अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कहते हैं कि 'यह एक औसत बजट है और कशषि सुधारों की इसमें कमी है। बजट में किए गए उपायों से कृषि क्षेत्र में नियमित विकास नहीं हो सकता है'। प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, फॉर्मस कमीशन के अध्यक्ष ने पाया है कि हमारी कृषि को लाभकारी बनाने में इस बजट में अवसर खो दिया गया है जबकि नेशनल एडवाइसरी काऊंसिल के कई सदस्यों ने इसे 'अकल्पनाशील' माना है और इस काऊंसिल की प्रमुख कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हैं।

ये सब अण्डरस्टेटमेंटस हैं। यदि इन स्वास्थ्य योजना पर एक नजर डालें तो नेशन वेक्टर वाली बीमारी के नियंत्रण कार्यकम में 23% की कमी, रूटीन टीकाकरण में 17% की कमी, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यकम में 11% और ट्रेकोमा तथा अंधेपन के नियंत्रण कार्यक्रम में 4% की कमी की गई है जिससे यह प्रभावित होता है कि यह बजट कृषि क्षेत्र के संकट को और बढ़ाएगा।

---

* संयुक्त सचिव, ऑल इण्डिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन और मेम्बर, सेन्ट्रल कमेटी, सीपीआई (एम)

भारत कृषक समाज, जबलपुर, (म.प्र.) ने 'कृषक शक्ति' पत्रिका का विमोचन किया

सैंकड़ों किसानों ने समाज के जबलपुर, (म.प्र.) में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें श्री अजय विश्नोई, मंत्री – पशुपालन एवं मत्स्य, (म.प्र.), डॉ० बलराम जाखड़, संरक्षक भारत कृषक समाज तथा डॉ० ध्यानपाल सिंह जी, सदस्य – म.प्र. राज्य कृषक आयोग, भोपाल पधारे। इस अवसर पर 'कृषक शक्ति' पत्रिका का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन में जिन लोगों ने भाग लिया तथा अपने विचार व्यक्त किए वह हैं : –

डॉ० बलराम जाखड़ – डॉ० जाखड़ ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। किसान ने देश को स्वावलम्बी बनाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने किसानों से आव्हान किया कि वे खेती का नक्शा बदल डालें। आधुनिक खेती से देश समृद्धशाली बनेगा।

श्री अजय विश्नोई – श्री विश्नोई ने मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह सरकार द्वारा किसानों के हित में किये जा रहे कार्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश किसानों को दिये जाने वाले बोनस में देश में अग्रणी है।

श्री मंगत सिंह खनूजा – उन्होंने आशा व्यक्त की कि कृषक शक्ति पत्रिका प्रदेश के किसानों की आवाज बनेगी। देश में भारत कृषक समाज के कार्यों की उन्होंने सराहना की तथा सभी किसान भाईयों को समाज का सदस्य बनने का अनुरोध किया।

श्री अजय जाखड़ – उन्होंने फिर से अपनी बात दोहराई कि भारत कृषक समाज किसानों की एक गैर–राजनीतिक तथा गैर–सांप्रदायिक संस्था है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध किया की वह राजनीतिक तथा जाति के मुददों पर किसानों को न बांटें।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज अपने सदस्यों के विवरण को अधतन करने की प्रकिया में हैं। सदस्यों को अपना पूरा नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ई–मेल आई.डी. यदि हो तो महासचिव, भारत कृषक समाज, ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली–110013 के पते पर भेजना आवश्यक है।